Central Council for Local Government & Urban Development and the Executive Committee of All India Council of Mayors urging upon the State Govts. to ensure early elections. Since holding elections to the municipalities/corporations is the concern of State Governments, the resolution has been forwarded to all the State Governments for necessary action.

Ban on cow slaughter

2496. SHRI SHANKAR SINH VAGHELA:

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE:

Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the state in which cow slaughter is banned, cow slaughter continues unabated due to loopholes in the ban-laws and many times cow are freighted by trucks and the railways to other States for slaughter; and

(b) if so, the estimated number of cows slaughtered during the last three years in different states year-wise?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF AGRICULTURE AND COOPERATION IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI YOGENDRA MAKWANA): (a) Preservation of cattle is a matter on which the State Legislatures have exclusive power to legislate. In accordance with that, various State Governments have enacted legislation relating to prevention of slaughter of cow and its progeny. The State Governments are requested from time to time to enforce the ban and that the same is not allowed to be circumvented by devious methods.

(b) The number of cows slaughtered during the year 1983 in different States/Union Territories excluding Manipur and Dadra & Nagar Haveli from whom information has not been received is 70501. Similar information in respect of 1984 and 1985 is not readily available and is being collected.

खाद्य तेलों के मूल्य में वृद्धि

2497. **श्री कल्पनाथ राय** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत तीन वर्षों के दौरान देश में खाद्य तेलों के मूल्यों में अत्यधिक वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) देश में खाद्य तेलों की कमी को पूरा करने के लिए क्या क्या कदम उठाये जा रहे हैं; और

(घ) क्या खाद्य तेलों का आयात करने, देश में ही उनका उत्पादन बढ़ाने और उनके मूल्य कम करने संबंधी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) खाद्य तेल, विशेष रूप से मूंगफली के तेल के मूल्य में अगस्त-सितम्बर, 1986 तक काफी वृद्धि हुई थी । तथापि, हाल में सरसों और मूंगफली के तेल के मूल्यों में गिरावट आई है ।

(ख) कुछ कारण हैं—सूखे के कारण वर्ष के दौरान तिलहनों के उत्पादन में गिरावट आना और मई से आरम्भ होने वाले कमी के मौसम का प्रभाव पड़ना ।

(ग) और (घ) सरकार खाद्य तेलों की मांग और इनके देशीय उत्पादन के बीच अन्तर को पूरा करने के लिए खाद्य तेलों का आयात कर रही है ।

सरकार ने तिलहनों और तेलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए कई उपाय

किए हैं । किए गए महत्वपूर्ण उपाय इस प्रकार हैं :—

(1) राष्ट्रीय तिलहन विकास परियोजना को कार्यान्वित करना, जिसमें दूसरे तिलहनों के बारे में गहन विकास कार्यक्रम चलाने के अतिरिक्त मूंगफली, रेपसीड/सरसों, सोयाबीन और सूरजमुखी के बारे में विशेष परियोजना चलाना शामिल है ।

(2) खाद्य तेलों और तिलहनों के उत्पादन ढ़ांचे को नया रूप देने और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के माध्यम से विपणन करने से संबंधित परियोजना के तहत कुछ राज्यों में राज्य स्तरीय सहकारी तिलहन उत्पादक संघ गठित किए हैं ।

(3) तिलहनों के लिये न्यूनतम समर्थन मूल्य उच्च स्तरों पर निर्धारित करके उत्पादकों को बेहतर प्रोत्साहन देना ।

(4) तिलहनों की उत्पादकता बढ़ाने के लिये अनुसंधान प्रयासों में तेजी लाना । तिलहनों के उत्पादन के बारे में एक प्रौद्योगिकी मिशन गठित किया गया है ।

(5) सोयाबीन और सूरजमुखी जैसी गैर-पारम्परिक तिलहनों की फसलों के अन्तर्गत क्षेत्र बढ़ाना और वृक्ष तथा वनमूल के तिलहनों, चावल की भूसी आदि का उपयोग करना ।

(6) तिलहनों के उत्पादन कार्यक्रम के अनुरूप संसाधन और आधार-ढ़ांचे संबंधी आवश्यक सुविधाओं की स्थापना करना ।

(7) वनस्पति उद्योग द्वारा गैर-पारम्परिक तेलों का अधिक प्रयोग करने पर वित्तीय प्रोत्साहन देना, परिष्कृत चावल की भूसी, बिनौले और सोयाबीन के तेल, जो सीधे मानव उपभोग के लिए हों, के संबंध में और परिष्कृत विलायक निष्कर्षित तेलों के लिये उत्पादन शुल्क से छूट देना ।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आयातित खाद्य तेलों का आवंटन कमी के मौसम और अधिकता वाले मौसम के अनुसार समायोजित किया जाता है, ताकि देशी खाद्य तेलों के मूल्यों को उचित स्तर पर बनाए रखा जा सके ।

Allotment of plot to Buddha Tri-Ratna Mission in Chittaranjan Park, New Delhi

2498. SHRI CHATURANAN MISHRA:

SHRI GURUDAS DAS GUPTA:

Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state

(a) whether Government have recently received some representation from Members of Parliament and Ex-Members of Parliament regarding the allotment of land in Chittaranjan Park, New Delhi for construction of a Buddha Vihar by the Buddha Tri-Ratna Mission;

(b) if so, the details thereof;

(c) whether the Ministry has instructed the Delhi Development Authority for incorporating such utilisation of a plot in Cittaranjan Park in the layout plan of the area;

(d) if so, the details thereof;

(e) whether Government are aware that in violation of instructions in this regard, the religious plot to be allotted in favour of the Mission has been sold out or is being sold at the rate of Rs. 30/- per sq. metre for residential purpose;

(f) if so, what action has been taken against those persons who are responsible for such sale; and